माननीय न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी के समक्ष

जगदीश राय और अन्य याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा विधान सभा सचिव, चंडीगढ़ और अन्य प्रतिवादी
1995 का सी. डब्ल्यू. पी. 6759
17 फरवरी, 2017

हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981-नियम । 11-नियम : निजी सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए सामान्य वरिष्ठता सूची निर्धारित करता है-व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक और संवाददाताओं के बीच सामान्य वरिष्ठता सूची की अनुपस्थिति में, केवल व्यक्तिगत सहायकों से की गई पदोन्नति-नियम 11 का उल्लंघन-राज्य का रुख मनमाना और भर्ती के नियमों के विपरीत है।

अभिनिर्धारित किया गया कि, नियम 1981 के तहत निजी सचिव के पद पर भर्ती की विधि निर्धारित करती है कि व्यक्तिगत सहायक के रूप में तीन साल का अनुभव या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक/रिपोर्टर के रूप में 8 साल का अनुभव और नियम 1981 का परिशिष्ट "बी" जो निर्धारित करता है कि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है।आधिकारिक प्रतिवादी ने 1981 से 1995 तक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करने का सहारा नहीं लिया है। इसके अलावा आधिकारिक प्रतिवादी वर्ष 1981 से 1995 के बीच निजी सचिव के पद पर केवल व्यक्तिगत सहायक को पदोन्नत कर रहे हैं।(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि कहा कि निजी सचिव के पद पर प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति दिनांक 20.4.1995 को अलग रखा गया है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति की तारीख से याचिकाकर्ताओं के नामों पर फिर से विचार करें और यदि वे अन्यथा पात्र हैं, तो उन्हें 20.4.1995 से पदोन्नत किया जाए और सभी सेवा और मौद्रिक लाभों का विस्तार किया जाए, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।आधिकारिक प्रतिवादी को आज से चार महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के नामों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।
(पैरा 13)

अमन चौधरी, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए।

हरीश राठी, सीनियर डी. ए. जी. हरियाणा।

नेहा जैन, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

न्यायमूर्ति पी.बी. बजंथरी (मौखिक)

2017 का सी. एम..2212
(1) आवेदन की अनुमति है जैसा कि अनुरोध किया गया है।अनुलग्नक आर-1/4 के साथ शपथ पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया है।

मुख्य मामला
(2) तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने 20.4.1995 दिनांकित आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था।उन्होंने निजी सचिवों के पदों पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने के लिए आधिकारिक प्रतिवादी को निर्देश देने की भी मांग की।

(3) याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 18.1.1978 और 21.3.1977 पर रिपोर्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को क्रमशः 22.10.1984 और 17.7.1991 पर व्यक्तिगत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निजी सचिव के पद को नियंत्रित करने वाली भर्ती के नियमों के साथ पठित सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, दोनों याचिकाकर्ता निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं जो निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए स्रोत कैडर में से एक है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि निजी सचिव के पद पर भर्ती का तरीका वरिष्ठता-सह-योग्यता है जो प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 (संक्षेप में "1981 नियम") के परिशिष्ट "बी" में विभिन्न पदों को भरने के लिए भर्ती की विधि प्रदान की गई है। निजी सचिव के पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने के उद्देश्य से, कॉलम संख्या 1 से 5 निम्नानुसार हैः

1	2	3	4	5

	निजी सचिव		तीन साल का अनुभव प्रिसोनल सहायक या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक/रिपोर्टर के रूप में आठ वर्ष	सभी वरिष्ठ अधिकारी, वाद-विवाद संपादक और निजी सचिवों की समान वरिष्ठता होगी - अधीक्षक पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से उनके संबंधित पदों में सेवा की अवधि संवाददाताओं, उपाधीक्षक और वरिष्ठ अनुवादकों के बीच कोई सामान्य अंतर-वरिष्ठता नहीं होगी और विभिन्न प्रभागों के अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति संबंधित प्रभागों के सदस्यों से सख्ती से की जाएगी। सामान्य प्रभाग, रिपोर्टिंग प्रभाग और अनुवाद प्रभाग अर्थात केवल वरिष्ठ अनुवादकों को ही अधीक्षक अनुवाद के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। केवल संवाददाताओं को वाद-विवाद के संपादक और अधीक्षक प्रकाशन के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और सामान्य विभाग में अधीक्षक के पद पर केवल सामान्य विभाग से संबंधित व्यक्ति को पदोन्नत किया जाएगा।

(5) यह आगे तर्क दिया गया कि आधिकारिक प्रतिवादी ने उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की है जिसमें व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक और रिपोर्टर शामिल हैं।यह भी तर्क दिया गया कि निजी सचिव के पद पर भर्ती का तरीका वरिष्ठता-सह-योग्यता है।आधिकारिक प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया है कि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार किया जाना आवश्यक है और उन्होंने वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंड को नजरअंदाज कर दिया है।उन्होंने पृष्ठ 13 पर आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा दायर शपथ पत्र से यह भी बताया है कि आधिकारिक प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी के दावे पर कैसे विचार किया है।यह स्पष्ट है कि उन्होंने वरिष्ठता-सह-योग्यता के तरीके पर विचार नहीं किया है और यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि अतीत में निजी सचिव का पद निजी सहायक के बीच भरा जा रहा है।

इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की पदोन्नति को दरकिनार किया जा सकता है।नतीजतन, आधिकारिक प्रतिवादी को निर्देश जारी किया जाए कि वे उत्तरदाता संख्या 3 और 4 की पदोन्नति की तारीख से निजी सचिव के कैडर में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें।

(6) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नामों पर विचार करते समय, याचिकाकर्ताओं के नाम और उनकी पात्रता पर ध्यान दें गया है और इस पर विचार किया गया है जैसा कि पृष्ठ 13 पर शपथ पत्र में कहा गया है जो नीचे दिया गया है। सरोज शर्मा, वरिष्ठ पी. ए., सर्वश्री सुभाष चंदर, पी. ; एस. के. भंडारी, मुख्य रिपोर्टर; शंभू नाथ, हिंदी रिपोर्टर; जगदीश राय, अंग्रेजी रिपोर्टर; और एस. एन. कादियान, अंग्रेजी रिपोर्टर नीचे दिया गया है।उपरोक्त अभिलेख के अवलोकन से पता चला है कि इन सभी अधिकारियों के पास 100% 'अच्छा' या 'अच्छा' एसीआर से बेहतर है।
चूंकि अतीत में निजी सचिव का पद नियमों के प्रावधानों के अनुसार पी. ए. को बढ़ावा देकर भरा गया है, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि श्रीमती. सरोज शर्मा, वरिष्ठ पी. ए., जो वरिष्ठ पी. ए./पी. ए. में सबसे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक/पी. ए./वरिष्ठ पी. ए. के रूप में अधिकारियों/माननीय उपाध्यक्ष के साथ काम करने का लगभग 14 साल का अनुभव रखते हैं, को निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है क्योंकि वह सेवा नियमों की आवश्यकता को पूरा करती हैं।यदि इस प्रस्ताव पर सहमति हो जाती है तो वरिष्ठ पी. ए. के परिणामी पद को भरने के प्रस्ताव पर बाद में अलग से विचार किया जाएगा।
उपरोक्त के अलावा, यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्री राम नारायण यादव की उप सचिव के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष के सचिव का पद 3 जनवरी, 1995 से खाली हो गया है।उक्त पद को भरा नहीं जा सका क्योंकि इसे हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियमों में शामिल नहीं किया गया है।हालांकि, उक्त पद को भरने के लिए योग्यता/अनुभव निर्धारित करने वाले आई. बी. आई. डी. नियमों में उक्त पद को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबे समय से लंबित है।प्रशासनिक हित में, प्रस्तावित योग्यताओं/अनुभव के आधार पर उक्त पद को भरने के लिए सरकार से एक सलाह मांगी गई है जो अभी भी जगदीश राय और अन्य बनाम हरियाणा विधान सभा है।

यदि अधिकारी सहमत होते हैं, तो पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 6.2 के ध्यान दें 2 के अनुसार अध्यक्ष के सचिव की रिक्त उच्च रिक्ति के खिलाफ निजी सचिव के कैडर में एक अतिरिक्त नियुक्ति की जा सकती है, जिसे नीचे दिया गया है, ताकि निजी सचिव को अस्थायी आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जा सकेः-
6.2 ..... हालांकि, निचली इकाई या संवर्ग में अतिरिक्त नियुक्तियों पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि उच्च श्रेणी में समान या अधिक रिक्तियों को भरा नहीं गया है।इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी कार्यालय की संख्यात्मक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है, उच्च इकाई या संवर्ग में प्रत्येक रिक्ति के लिए निचली इकाई या संवर्ग में केवल एक अतिरिक्त पद स्वीकार्य है।

नोट 2:- निम्न श्रेणी में अतिरिक्त नियुक्ति, जिसे राजपत्रित क्षमता में उच्च श्रेणी में खाली छोड़ी गई रिक्ति के खिलाफ समायोजित किया जाना है, राजपत्रित या गैर-राजपत्रित प्रकृति की हो सकती है।"

यदि उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति हो जाती है, तो श्री सुभाष चंदर, पी. ए. का नाम, जो श्रीमती के बगल में है। सरोज शर्मा, वरिष्ठ पी. ए.वरिष्ठता में, विशेष वेतन के रूप में निजी सचिव के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, वर्तमान के लिए, अस्थायी आधार पर, ऊपर निर्दिष्ट नियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष के सचिव की रिक्त उच्च रिक्ति के खिलाफ।श्री सुभाष चंदर, पी. ए. की ए. सी. आर. एस. 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि के लिए भी देखी गई है और यह पाया गया है कि 4 जुलाई, 1991 को जारी एक 'प्रशंसा पत्र' के अलावा 'अच्छी' रिपोर्ट, दो 'बहुत अच्छी' रिपोर्ट और चार 'उत्कृष्ट' रिपोर्ट हैं, जैसा कि नीचे दिए गए ए. सी. आर. के सारांश से स्पष्ट है।यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है और श्री सुभाष चंदर, पी. ए. को निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो पी. ए. की परिणामी रिक्ति को भरने के प्रस्ताव की जांच की जाएगी और बाद में अलग से रखा जाएगा।

(7) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एक संवर्ग में वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 व्यक्तिगत सहायक संवर्ग से हैं और निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से संवर्ग का पहला स्रोत व्यक्तिगत सहायक है।इसलिए निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तिगत सहायकों पर विचार किया जाना आवश्यक है।यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास निजी सचिव के अलावा पदोन्नति के अन्य अवसर हैं और वे विचाराधीनता की आयु प्राप्त कर चुके हैं और मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।इसलिए, यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में समानता पर भी ध्यान दें सकता है।

(8) प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है और प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो गई है।इसलिए, जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 का संबंध है, याचिका को समाप्त कर दिया गया है।

(9) विद्वान वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 का चयन और नियुक्ति निजी सचिव के पद को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में है।वरिष्ठता को एक विशेष संवर्ग के संदर्भ में लिया जाना आवश्यक है न कि संयुक्त वरिष्ठता सूची के संदर्भ में।इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संयुक्त वरिष्ठता सूची को बनाए रखा जाना चाहिए, बनाए रखने योग्य नहीं है।निजी सचिव के पद के लिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नामों पर आगे विचार करना व्यक्तिगत सहायक संवर्ग और वरिष्ठता के नियम 11 के रूप में विभाग द्वारा बनाए गई वरिष्ठता के संदर्भ में है जो बहुत विशिष्ट है कि प्रत्येक संवर्ग वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता है।इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 दिनांकित 20.4.1995 की पदोन्नति के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।

(10) पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता सुनी।

(11) नियम 1981 के तहत निजी सचिव के पद पर भर्ती की विधि निर्धारित करती है कि व्यक्तिगत सहायक के रूप में तीन साल का अनुभव या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक/रिपोर्टर के रूप में 8 साल का अनुभव और नियम 1981 का परिशिष्ट "बी" जो निर्धारित करता है कि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से सामान्य

वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है।कानून के उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए।प्रतिवादी को व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक और रिपोर्टर की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करने की आवश्यकता होती है।आधिकारिक प्रतिवादी ने 1981 से 1995 तक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करने का सहारा नहीं लिया है।इसके अलावा आधिकारिक प्रतिवादी केवल जगदीश राय और अन्य बनाम हरियाणा विधान सभा को बढ़ावा दे रहे हैं।

दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सहायक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ अच्छे संबंध में हैं ताकि केवल उनके नामों पर विचार किया जा सके।मान लीजिए, जिन व्यक्तियों को 1981 से 1995 तक निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है, वे केवल व्यक्तिगत सहायकों के स्रोत संवर्ग से हैं।आधिकारिक प्रतिवादी ने वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक और रिपोर्टर के दावे की अनदेखी की है।1981 से 1995 की अवधि के दौरान, एक वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक या रिपोर्टर को भी पदोन्नत नहीं किया गया था।इस मुद्दे पर, विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि संवाददाताओं के पास पदोन्नति के अन्य रास्ते हैं।इसलिए उनके नाम पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।यह तर्क वर्तमान मामले के लिए अप्रासंगिक है।इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि कोई व्यक्तिगत सहायक नहीं है, तो ऐसे आयोजन में वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक को पदोन्नत किया जाता है और यदि कोई वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक उपलब्ध नहीं है तो रिपोर्टर।उस विधि में, नियमों में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए निजी सचिव के पद को भरा जाना आवश्यक है।यह तर्क इन कारणों से सोचा गया है कि याचिकाकर्ता के नाम पर भी विचार किया गया था जैसा कि शपथ पत्र से स्पष्ट है।नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि यदि व्यक्तिगत सहायक उपलब्ध नहीं हैं तो वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक और यदि वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक उपलब्ध नहीं हैं तो रिपोर्टर।इसलिए, विद्वान राज्य वकील की प्रस्तुति को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।इसके अलावा, पृष्ठ Nos.10 से 15 पर शपथ पत्र के साथ उत्तरदाता संख्या 3 और 4 के बराबर याचिकाकर्ताओं के नामों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने निजी सचिव के पद पर भर्ती के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की है जो वरिष्ठता-सह-योग्यता है।जबकि निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए उत्तरदाता संख्या 3 और 4 के नामों पर विचार करते समय, प्रतिवादी का विचार है कि सबसे योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत सहायक संवर्ग से सर्वश्रेष्ठ और योग्य का चयन 1981 से 1995 तक किया गया है।राज्य और प्रतिवादी संख्या 4 का रुख अत्यधिक मनमाना और भर्ती के नियमों के विपरीत है।

(12) समता के प्रश्न पर, उच्चतम न्यायालय के मामले में
डॉ.एम.एस. पाटिल बनाम गुलबर्गा विश्वविद्यालय और अन्य; (2010) 10 एससीसी 63) ने माना कि यदि एक न्यायालय के समक्ष अवैध आदेश पर सवाल उठाया जाता है, समता का सवाल नहीं उठता है और आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में गंभीर कमी होने पर चयन और नियुक्ति को दशक के बाद भी अलग रखा जा सकता है।

(13) इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निजी सचिव के पद पर प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति दिनांक 20.4.1995 को अलग कर दिया गया है।प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति की तारीख से याचिकाकर्ताओं के नामों पर फिर से विचार करें और यदि वे अन्यथा पात्र हैं, तो उन्हें 20.4.1995 से पदोन्नत किया जाए और सभी सेवा और मौद्रिक लाभों का विस्तार किया जाए, इस

तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।आधिकारिक प्रतिवादी को आज से चार महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के नामों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

(14) याचिका की अनुमति है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा